भारत की स्वास्थ्य गतिशीलता (बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन) 2022-23

स्वास्थ्य मंत्रालय ने "भारत की स्वास्थ्य गतिशीलता (बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन) 2022-23" जारी की

प्रमुख बिंदु

- **जारीकर्ता:** केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने "भारत की स्वास्थ्य गतिशीलता (बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन) 2022-23" जारी की है।
- यह एक वार्षिक प्रकाशन है जिसे पहले **"ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी"** के नाम से जाना जाता था।
- **प्रकाशन तिथि:** यह दस्तावेज़ 1992 से प्रकाशित हो रहा है।
- यह एक मूल्यवान दस्तावेज है जो **एनएचएम के अंतर्गत जनशक्ति और बुनियादी ढांचे के बारे में अत्यंत आवश्यक जानकारी** प्रदान करता है, तथा नीति निर्माण, प्रक्रियाओं में सुधार और समस्या समाधान में सहायक है।
- 1992 से, प्रकाशन ने स्वास्थ्य अवसंरचना और मानव संसाधनों पर विस्तृत वार्षिक डेटा प्रदान किया है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपडेट किया जाता है। यह डेटा स्वास्थ्य क्षेत्र के हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश भर में स्वास्थ्य अवसंरचना की प्रभावी योजना, निगरानी और प्रबंधन का समर्थन करता है।

I4C स्थापना दिवस

10 सितंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के पहले स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया।

प्रमुख बिंदु

- **सीएफएमसी की स्थापना नई दिल्ली स्थित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में की गई है।**
- इसमें प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना **अक्टूबर 2018** में गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत की गई थी।
- **समन्वय- वेब आधारित मॉड्यूल:** समन्वय नामक वेब आधारित मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया है। यह साइबर अपराध डेटा संग्रह, साझाकरण, मानचित्रण और विश्लेषण के लिए एक मंच है, साथ ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए समन्वय उपकरण भी है।
- **'साइबर कमांडो' कार्यक्रम:** 'साइबर कमांडो' कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया गया है, जिसके तहत साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय पुलिस संगठनों में प्रशिक्षित विशेषज्ञों की एक शाखा स्थापित की जाएगी।
- **संदिग्ध रजिस्ट्री:** संदिग्ध रजिस्ट्री का भी अनावरण किया गया है। यह बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों के सहयोग से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर आधारित पहचानकर्ताओं की एक रजिस्ट्री बनाकर धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को मजबूत करने की एक नई पहल है।

5वीं भारत-फिलीपींस जेडीसीसी बैठक

रक्षा सचिव मनीला में 5वीं भारत-फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसी) बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे।

प्रमुख बिंदु

- रक्षा सचिव 11 सितंबर, 2024 को मनीला में भारत-फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (जेडीसीसी) की पांचवीं बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे।
- बैठक की सह-अध्यक्षता फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अवर सचिव श्री इरिनियो क्रूज़ एस्पिनो द्वारा की जाएगी।
- **जेडीसीसी स्थापना:** जेडीसीसी की स्थापना 2006 में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत की गई है।

- **पूर्व संस्करण:** जेडीसीसी बैठक का चौथा संस्करण मार्च 2023 में नई दिल्ली में संयुक्त सचिव स्तर पर आयोजित किया गया था।
  - पांचवें संस्करण में सह-अध्यक्ष को सचिव स्तर पर पदोन्नत किया गया है।

यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि **भारत और फिलीपींस अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ तथा भारत की एक्ट ईस्ट नीति की 10वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।**

दोनों देशों के बीच सशक्त और बहुआयामी संबंध हैं, जो रक्षा और सुरक्षा सहित कई रणनीतिक क्षेत्रों तक विस्तारित हो गए हैं।

वे रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

54 वीं जीएसटी परिषद की बैठक

9 सितंबर 2024 को 54वीं वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक की अध्यक्षता **भारत के वित्त मंत्री** ने की।
- बैठक का **प्राथमिक लक्ष्य** यह सुनिश्चित करना था कि संग्रह दक्षता में सुधार किया जा सके और नागरिकों के लिए प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित किया जा सके।

महत्वपूर्ण एजेंडा:

पैनल द्वारा विचार हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

- **जीओएम- चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा पर:** वित्त मंत्री ने घोषणा की कि परिषद ने चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर में कटौती पर एक नया मंत्री समूह (जीओएम) बनाने का फैसला किया है। इसकी अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन इस सीमित उद्देश्य के लिए इसमें नए सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। यह अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- **कैंसर की दवाओं पर जीएसटी:** कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका उद्देश्य कैंसर के इलाज की कुल लागत को और कम करना है। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य नागरिकों की मदद करना है।

- **उपकर पर मंत्रियों का समूह:** बैठक के दौरान बताया गया कि मार्च 2026 तक कुल उपकर संग्रह 8.66 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इसके अलावा, ऋण भुगतान निपटाने के बाद, लगभग 40,000 करोड़ रुपये का अनुमानित अधिशेष होने की उम्मीद है। चुनिंदा स्नैक्स सस्ते होने वाले हैं: जीएसटी परिषद ने चुनिंदा स्नैक्स पर कर को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने का फैसला किया है। यह आम नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है।
- **सरकारी विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों के लिए छूट:** केंद्र या राज्य सरकार के कानूनों के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों और शोध केंद्रों, या जिन्हें आयकर छूट दी गई है, को अब शोध निधि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि ये संस्थान जीएसटी के लिए उत्तरदायी हुए बिना सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से शोध निधि प्राप्त कर सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जिसका उद्देश्य देश की शोध क्षमताओं को बढ़ावा देना है।
- **एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर पर:** जीएसटी पैनल ने राजस्व के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया, जो नकारात्मक आईजीएसटी शेष की समस्या का समाधान करेगी तथा राज्यों को वितरित अतिरिक्त आईजीएसटी की वसूली पर ध्यान केंद्रित करेगी।

- **बी2सी जीएसटी चालान:** जीएसटी पैनल ने बिजनेस-टू-कस्टमर (बी2सी) जीएसटी इनवॉइसिंग शुरू करने का फैसला किया है। जीएसटी इनवॉइस प्रबंधन की यह प्रणाली 1 अक्टूबर से लागू होगी।
- **कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:** बैठक में कार सीटों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की भी घोषणा की गई। इसके अलावा, पैनल ने यह भी स्पष्ट किया कि रेलवे के लिए रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट (आरएमपीयू) एयर कंडीशनिंग मशीनों को एचएसएन 8415 के तहत वर्गीकृत किया जाएगा, जिस पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू होगी। इसके अलावा, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, इस निर्णय के बारे में अधिक स्पष्टता और विवरण की प्रतीक्षा है।

संसदीय राजभाषा समिति

अमित शाह पुनः संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष चुने गए।

प्रमुख बिंदु

- गृह मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है। वे 2019 से 2024 तक इस समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं।
- **गठन:** संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत 1976 में किया गया था।
- **सदस्य**: समिति में **30 संसद सदस्य शामिल हैं, जिनमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से** हैं।

लघु समाचार - उत्तर प्रदेश

- हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में **73 वें अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया।** इस प्रतियोगिता में देश भर के केन्द्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 34 पुलिस बल टीमें भाग ले रही हैं।

- सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को **2019 में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (एटीआरई) के माध्यम से चयनित 69,000 सहायक शिक्षकों की संशोधित सूची तैयार करने को कहा गया था।**
  - मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने रवि कुमार सक्सेना और 51 अन्य की याचिका पर राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव सहित अन्य को नोटिस भी जारी किए।

सैन्य अभ्यास

युद्ध अभ्यास-2024

भारत-अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास

- भारत-अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास-2024 का 20वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है।
- यह अभ्यास 9 से 22 सितंबर 2024 तक आयोजित किया जाना है।
- यह वर्ष 2004 से प्रतिवर्ष भारत और अमेरिका के बीच बारी-बारी से आयोजित किया जाता रहा है।
- इस संस्करण में सैन्य शक्ति और उपकरणों के संदर्भ में संयुक्त अभ्यास के दायरे और जटिलता में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।
- युद्ध अभ्यास दोनों पक्षों को संयुक्त अभियान चलाने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाएगा। इससे दोनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल, सौहार्द और सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने में मदद मिलेगी।

संयुक्त अभ्यास से रक्षा सहयोग भी बढ़ेगा और दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में और वृद्धि होगी।

खेल

यूएस ओपन टेनिस 2024

- 2024 यूएस ओपन टेनिस का **144 वां संस्करण और वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम इवेंट** था।
- यह **न्यूयॉर्क शहर के यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर** में आउटडोर हार्ड कोर्ट पर आयोजित किया गया था।
- इस आयोजन के 144 वें संस्करण का जश्न मनाने के लिए, यूएस ओपन ने इस वर्ष की कला थीम, **द पावर ऑफ टेनिस** पर आधारित 2024 का पोस्टर बनाने के लिए कलाकार और ग्राफिक डिजाइनर चेल्सी फैरिस का चयन किया।

विजेताओं की सूची:

- **यूएस ओपन 2024 पुरुष एकल चैंपियन:** जैनिक सिनर ने अमेरिकी खिलाड़ी टेलर फ्रिट्ज़ को सीधे सेटों में हराकर अमेरिकी ओपन जीतने वाले पहले इतालवी पुरुष बनकर इतिहास रच दिया।
- **यूएस ओपन 2024 महिला एकल चैंपियन:** आर्यना सबालेंका (वह अमेरिकी ओपन जीतने वाली पहली बेलारूसी खिलाड़ी बनीं और स्टेफी ग्राफ, मोनिका सेलेस, एंजेलिक केर्बर और मार्टिना हिंगिस जैसी दिग्गज खिलाड़ियों के अलावा एक ही वर्ष में ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकी ओपन जीतने वाली पांचवीं महिला बनीं।)

- **यूएस ओपन 2024 पुरुष युगल चैंपियन:** मैक्स परसेल और जॉर्डन थॉम्पसन
- **यूएस ओपन 2024 महिला युगल चैंपियन:** जेलेना ओस्टापेंको और ल्यूडमिला किचेनोक
- **यूएस ओपन 2024 मिश्रित युगल चैंपियन:** सारा इरानी और एंड्रिया वावासोरी

अन्य राज्यों से महत्वपूर्ण समसामयिकी

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों के नए सिरे से सीमांकन के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया है। सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इस आयोग को नागरिक सुझाव दे सकेंगे।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगा जिसमें जनजातीय छात्रों के लिए 80% आरक्षण होगा।

नई दिल्ली

भारत 11 से 12 सितम्बर तक नई दिल्ली में नागरिक विमानन पर दूसरे एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है।

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध अगले साल 1 जनवरी तक लागू रहेगा।

उत्तराखंड

नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस (एनसीजीजी) ने मसूरी में मालदीव के सिविल सेवकों के लिए 33वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) की शुरुआत की। 9 से 20 सितंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा दो सप्ताह का कार्यक्रम विदेश मंत्रालय (MEA) के सहयोग से किया जा रहा है। मालदीव के 1,000 सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के नवीनीकरण के बाद मालदीव के सिविल सेवकों के लिए दूसरे चरण के तहत यह पहला कार्यक्रम है।

विविध

❖ **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय** द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, **जुलाई 2024 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) 1.3 अंक बढ़कर 142.7 पर पहुंच गया।**

➢ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय, श्रम ब्यूरो, देश के 88 औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण केन्द्रों में फैले 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा कीमतों के आधार पर हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित करता रहा है।

❍❍❍❍